(d) if not what arrangements have been made to provide continuous technical assistance, and to produce and deliver products without delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir. A few Sanskrit institutions have initiated computer based Sanskrit studies education and research under the Technology Development for Indian Languages (TDIL) Programme of the Department of Electronics.

(b) Under the TDIL Programme, resource centres for computer assisted Sanskrit teaching and learning have been established. They are expected to provide assistance to the Sanskrit institutions. The computer assisted Sanskrit teaching and learning programme has also been initiated for the benefit of Sanskrit Scholars.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

उर्वरकों की दोहरी मूल्य नीति के प्रति सकारात्मक तथा नकारात्मक रवैया रखने वाले राज्य

1682. **श्री शिव प्रताप मिश्र :**

श्री दिनेश भाई त्रिवेदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने उर्वरकों की दोहरी मूल्य नीति के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं ;

(ख) किन-किन राज्यों ने यह कहा है कि दोहरी मूल्य नीति अव्यवहारिक है तथा केन्द्रीय सरकार इन राज्यों में इस नीति को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ग) किस तरह से छोटे तथा सीमान्त किसानों की पहचान की जाएगी ; और

(घ) क्या सरकार छोटे तथा सीमान्त किसानों को खाद पर पूर्ण राज-सहायता देने के लिए राज्यों को आदेश देने का विचार रखती है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, मणीपुर, कर्नाटक, केरल, मध्य-प्रदेश, हिमाचल-प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडीसा, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दिल्ली और दमन एवं दीव के संघ राज्य क्षेत्रों ने उर्वरक के लिए दोहरी मूल्य नीति के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं ।

(ख) अधिकांश राज्यों ने उर्वरक की दोहरी मूल्य नीति को कार्यन्वित करने में कठिनाई व्यक्त की है । तथापि, मार्गदर्शन जो राँज्यों के परामर्श से तैयार किए गए थे, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए हैं । कुछ मानदण्डों के अन्तर्गत योजना तैयार करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त शिथिलता प्रदान की गयी हैं ।

(ग) एक हैक्टेयर तक की भूमि धारण करने वाले किसानों को सीमान्तरीय किसान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 2 हेक्टेयर तक भूमि धारण करने वाले किसानों को लघु किसानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । राजस्व रिकार्डों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा शिनाख्त की जाएगी।

(घ) चालू वर्ष के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 405 करोड़ रु० की राशि रखी गयी है।

Hiring of building of the Ministry of Science & Technology

1683. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Science and Technology had hired the building of Bhuvalaka Jan Kalyan Trust in Calcutta several years ago;